जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना पुस्तिका का विमोचन

योजना के तहत आगामी दो वर्षों में मिलेगें 60 हजार घरेलू कनेक्शन

जयपुर, 30 अक्टूबर। ऊर्जा मंत्री डा0 जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विद्युत भवन में मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित) के लिए तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित) के तहत 100 व उससे कम आबादी की ढाणियों में घरेलू कनेक्शन देने बाबत जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य सूचनाओं को समाहित किया गया है।

इस अवसर पर डा0 सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2012–13 में की गई घोषणा के अनुसार 100 व उससे कम आबादी की ढाणियों में आगामी दो वर्षों में पांच–पांच के समूह में 60 हजार घरेलू कनेक्शन दिए जाएगें। इसके लिए वितरण तंत्र की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 1 नवम्बर, 2012 से इस योजना के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी। आवेदन के साथ केवल 200 रुपए प्रति कनेक्शन आवेदन राशि ही ली जाएगी तथा आवेदन पांच के समूह में ही स्वीकार किए जाएगें। उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रति कनेक्शन पर होने वाले खर्च में 50 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी तथा आवेदक द्वारा मात्र 3500 रुपए मांग राशि के रुप में ही देय होंगे।

उन्होंने बताया कि 300 से अधिक आबादी की ढाणियों का लगभग विद्युतीकरण हो चुका है तथा शेष कार्य दिसम्बर, 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। 100 से 300 की आबादी की ढाणियों के विद्युतीकरण के लिए 1350 करोड़ रुपए लागत की 25 योजनाएं केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी हुई है।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार गांवों से खेतों पर रहने चले गए परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने के कार्य का राज्य सरकार द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है, सर्वे के बाद इसकी कार्य योजना बनाकर केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।

इसके साथ ही आज ऊर्जा मंत्री डा0 जितेन्द्र सिंह ने प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता एवं आपूर्ति की समीक्षा के लिए भी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी की फसल के लिए किसानों को निर्धारित 6 घंटे के ब्लॉक में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रखी जावे। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 1675 लाख यूनिट बिजली की मांग की तुलना में करीब 200 लाख यूनिट बिजली की कमी बनी हुई है। इस कमी को खरीदकर एवं बैंकिग के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विद्युत निगमों को 1365 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिए गए है।

डा0 जितेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि रबी की फसल के दौरान प्रत्येक सहायक अभियन्ता कार्यालय में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखवाये जाने की व्यवस्था की जावे ताकि ट्रांसफार्मर के जलते ही तुरन्त बदलने की व्यवस्था की जा सके।

समीक्षा बैठक में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक शैलेन्द्र अग्रवाल, विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष कुंजीलाल मीणा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पी.एन.सिंहल, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी एवं निदेशक पावर ट्रेडिंग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 363/2012 ––––